श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप सभापति जी से यह भी निवेदन कर दें कि 12 बजे के बाद 15 मिनट तक वे सदन में और ठहरें । यह आश्वासन आप दे दें।

श्री उपसभापति : ठीक है।

SHRI S. W. DHABE: Sir, this is a very important matter. This is in regard to interpretation of rules 187, 188 and 189. We do not agree with the interpretation given by one hon. Member that consent means, everybody should be asked. Hence, my suggestion to you is that, in order to cut short the whole thing, you should convey our strong feelings to the Chairman and he should be present in the House. This question should be discussed in the House so that all Members can partidipate in it. By this way, a procedure can be evolved. This should be discussed tomorrow. Kindly convey our strong feelings to the Chairman. This is all.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported racket involving pilferage of 50 barrels of lubricating oil worth Rs. 1 lakh daily from the Indian Oil Corporation's pipeline running between Manali Refinery and the Madras Port —*contd.*

श्री उपसभापति : श्री कल्पनाथ राय जी, समय बहुत हो गया है । इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए । मै माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वे कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति जी, मैंने सवाल किया था कि यह जो एक लाख रुपये मूल्य के लुब्रीकेटिंग आयल की पर डे चोरी होती है, क्या इसके पहले भी इस तरह की चोरी का पता लगाया गया था ? यदि हाँ, तो इसका क्या नतीजा हुआ सरकार ने दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार बताएगी कि यह चोरी कब से हो रही है और पाइप लाइन में वह कौन सा स्थान है जहाँ चोरी होती है ? सरकार ने पाइप लाइन की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है । क्या इस चोरी में रिफाइनरी में काम करने वाले अफसरों का भी हाथ है ? क्या पाइप लाइन में चोरी के तेल का हिसाब होता है या नहीं । टोटल प्रोफिट लास एकाउन्ट में पिलफ्रेज की मात्रा कितनी है ? क्या सरकार सी० बी० आई० के माध्यम से इस चोरी की इन्क्वायरी कराएगी । क्या सरकार रेलवे पब्लिक अन्डरटेकिंग एवं स्टील पब्लिक अन्डरटेकिंग की तरह से पैट्रोलियम के लिए भी सिक्योरिटी की व्यवस्था कराएगी क्योंकि इसमें सरकार के अरबो रुपयो का इंवोल्वमेन्ट है । क्या सरकार यह भी बतलाएगी कि इतनी चोरी जब सन् 1976 से आपके अनुसार हो रही है, तो इसमें कितने कर्मचारी पकड़े गये और कितनों को दंडित किया गया : इस चोरी के अलावा सन् 1976 से आज तक इस तरह की चोरी की कितनी घटनाएं हुई है क्या पैट्रोलियम मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ बात करके किसी प्रकार से सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करने जा रही है। चूंकि रेलवे मंत्रालय की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है और उसी तरह से स्टील मंत्रालय की भी अपनी सिक्योरिटी फोर्स है, इसलिए पैट्रोलियम में जब कि सरकार का अरबों रुपया लगा हुआ है और यह इतना बड़ा मंत्रालय है तो सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? श्रीमन्, मैंने ये सारे प्रश्न सरकार के सामने रखे है । इस मामले

में एक लाख रुपये की कीमत के आयल की चोरी एक साल में हुई है, यह सरकार स्वीकार कर चुकी है। यह पिलफ्रेज सन् 1976 में हुई है। हिन्दुस्तान में बहुत सी रिफाइनरीज है, पाइप लाइन्स लगी हुई है। अगर इस तरह की चोरी होगी तो उससे सरकार को बहुत हानि होगी। प्रधान मंत्री जी ने वैज्ञानिकों की एक मीटिंग में कहा है कि हमें अन्य सोर्स आफ एनर्जी को प्राथमिकता देनी है। पैट्रोलियम भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सोर्स आफ एनर्जी है ध्यान देने की बात यह है कि हमको टू-थर्ड हिस्सा पैट्रोलियम का विदेशों से मंगाना पड़ता है। आपने 50 सौ करोड़ रुपये उसमें खर्च कर दिया है, तो इस तरह से पिलफरेज के माध्यम से करोड़ों रुपये की चोरी होती है और इस तरह से देश की एकानमी बरबाद हो रही है तो मै मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में क्या सरकार कोई ठोस और समय-बद्ध कार्यक्रम अपनायेगी ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो!

श्री दर्बार सिंह: डिप्टी चैयरमेन साहब, मेम्बर साहबान श्री कल्पनाथ राय जी ने यह पूछा है कि इसका पता लगाया है कि नहीं कि कब से हो रहीं है और इसकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया है या नहीं, अब तक करते रहे है या नहीं। यह जो मैंने स्टेटमेन्ट पढ़ा है उसके अन्दर ये सारी चीजें मैंने तफसील से बताई है कि 1976 से हो रही है और 1976 के बाद कितनी दफा ही स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस कमिश्नर जो है उनसे कहा और कितनी दफे ही ये सारी बातें उनके नोटिसेज में लाये है क्योंकि सिक्युरिटी ला एंड आर्डर की बात है और वह सारी स्टेट गवर्नमेन्ट की है। स्टेट गवर्नमेन्ट से बातचीत करके 51 पुलिस के आदमियों की वहां पर ड्यूटी है। लेकिन इसके बावजूद यह चीज होती रही। ऊपर नहीं, कुछ ऐसे स्पाट है जैसे मैंने बताया कि 4 किलोमीटर यह पाइप लाइन है अन्डरग्राउन्ड और बाकी 5.3 ऊपर की है। तो जो नीचे, अन्डर ग्राउंड है वहां पर उन्होंने एक झोंपड़ी बना ली और झोंपड़ी बना कर उसके नीचे यह नहीं पता लगा कि यह झोंपड़ी है और उसके नीचे गड्ढा गोद लिया। जब वह गड्ढा नोटिस में आया तब इसका पता लगा। इस तरह से इसमें और भी वाकये होते रहे है। इन्होने पूछा कि अब तक कितने केसेज हुए है। केसेज अभी तक जनवरी 1979 दिसम्बर से 1979 तक 76 हुए, 121 कनविक्ट हुए और जुलाई 1980 तक नम्बर आफ केसेज रजिस्टर्ड-85, नम्बर आफ अरेस्ट मेड-170-40, कनविक्टेड इसके अन्दर इतने ऐक्शन लेने के बावजूद ये चीजें होती रहीं। जैसा कि मैंने हाउस को यकीन दिलाया है कि वहां पर चेयरमैन, आइ०ओ०सी० जाकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आन दि स्पाट चेक करेंगे, हमारे यहां से सीनियर आफिसर जाकर आन दि स्पाट देखेंगे और जो रेमिडियल मेजर्स पासिबल हो सकते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसका पूरा इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा जो बातें आई है, मेम्बर साहबान जो महसूस करते है उसमें मैं उनके साथ हूं कि उसका इंतजाम पूरी तरह से इसको चैक करने के लिये किया जाना चाहिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): उपसभापति महोदय, यह जो मद्रास रिफाइनरी है, भारत सरकार के विभागीय नियंत्रण के अन्तर्गत तेल साफ करने की जो ऐसे सरकारी संस्थान है उसमें यह एम० आर० एल०, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड जो है इसमें सरकारी पूंजी 74 प्रतिशत है और 26 प्रतिशत पूंजी ईरान और अमेरिकी सरकार की लगी हुई है और इस

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

तरह से यह कम्पनी काम कर रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 1976 से इसमें चोरी हो रहीं है और 1976 से सरकार के जरिये कार्यवाही करने का जहाँ तक सवाल है, और समय में और बात थी, लेकिन 1975-76 तो वर्तमान सरकार के लिये सबसे उपयोगी समय था, जिस समय कि कई लोगों को पकड़कर जबर्दस्ती मीसा में जेल में ठूस दिया गया था चोर और बदमाश के नाम पर इन तेल कम्पनियों में तेल चुराने वाले आदमियों को 1975-76 में इमरजेंसी के समय में इन बदमाशों की यह सरकार नहीं पकड़ सकी तो जरुर इससे यह अन्दाजा लगता है कि वे चोरी करने वाले लोग जो हैं उनको बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उस कम्पनी में काम करने वाले जो बड़े अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है उस संरक्षण में वह चोरियां वहाँ होती रही है। तो मै सरकार से यह जानना चाहूंगा कि 1976 से जो चोरी हो रहीं थी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पुलिस ने यह कर दिया, फलाने ने यह कर दिया इस कम्पनी ने 1978-79 तक 69.9 मिलियन रुपये मुनाफा कमाया है। यह भी देखने की बात है कि 1976 से चोरी हो रही है तेल वहाँ पर चोरी होने के बावजूद भी 69.9 मिलियन रुपये इस कम्पनी ने मुनाफा कमाया है उसमें से 15% डिविडेंड फंड में भी उसने दिया फिर यह भी देखने की बात है कि यह कम्पनी तेल साफ करती है। इस तेल की खरीद करता है आई०ओ०सी० और आई० ओ० सी० वितरण करता है। इस कम्पनी का काम है केवल तेल शोधन करना। वितरण करने का काम उस कम्पनी से तेल लेकर आइ० ओ० सी० द्वारा होता है तो यह कोई नहीं है कि केवल इसमें एम०आर०एल० कम्पनी संलग्न है बल्कि इससे आई०ओ०सी० का भी संबंध हो जाता है। जितन तेल इस कम्पनी के पास साफ होने को गया होगा, और जितना तेल साफ होने के बाद आइ०ओ०सी ने खरीद किया क्या कभी इस खाते को भी मिलाने का काम किया गया या नहीं ? दूसरा यह कि जो सरकार की पब्लिक इंटरप्राइजेज है इनका आडिट होता है। इस आडिट में क्या इन बातों को भी पकड़ा गया, इन जाँच पड़तालों में क्या कभी यह बात आई है या नहीं ? इसमें एक लिमिटेड परसेंटेज होता है कि इतना तेल होगा, इसमें इतनी गन्दगी निकल जाएगी, इतना रिफांइन्ड तेल निकल जाएगा। वह परसेंटेज कभी पकड़ में आया या नहीं आया ? अगर नहीं आया तो यह साफ जाहिर है कि बड़े अधिकारी, जाँच करने वाले अफसर जो रहे है उनका भी इसमें हाथ रहा है क्योंकि उस मामले को कहीं न कहीं छिपाने का काम होता रहा है अगर उस परसेंटेज से तेल कम हो तो कहाँ चला गया। यह खोजा जाना चाहिए था, परन्तु नहीं खोजा गया। क्या इसकी कभी खोजबीन हुई, आडिट में पकडा गया या नही, विभागीय जाँच हुई उसमें पकड़ा गया या नहीं ? अगर पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कोइ कार्यवाही की गई या नहीं की गई (*Time bell rings*) यहाँ पर मैं एक और यह भी बता देना चाहता हूं मुझे केवल एक दो प्रश्न करने हैं।

श्री उपसभापति : प्रश्न कीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : प्रश्न कर रहा हुं। इस कम्पनी को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए, एम० आर० एल० के विस्तार के लिए सरकार ने 54.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है इसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। जिस समय यह

क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने मंजूरी दी होगी उस समय यह क्षमता बढ़ाने वाली टीम गई होगी। उसने जरूर जाँच की होगी कि उसका पाईप-लाईन कितना मोटा होगा कितना तेल उसमें पास किया जाएगा, पाइप-लाइन को कहाँ बदला जाएगा, कितने चेजेज होंगे। सारी डिटेल्स में इन्क्वायरी करने के बाद कि विस्तार की योजना में क्या क्या होगा यह 54.78 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय क्या यह बात डिटेक्ट हुई या नहीं हुई? अगर डिटेक्ट नहीं हुई तो विस्तार के लिए जो योजना बनाई गई थी वह योजना भी कागजी रही होगी। इस योजना के डिटेल्स में जाने का काम तकनीशियनों ने नहीं किया। यह भी सरकार को बताना चाहिए कि उसमें यह सब इन्क्वायरी हुई थी या नहीं? यह फिर मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि तेल पाइप जहाँ दिए गए है वहाँ पर जगह जगह पर तेल पाइप की जाँच करने के लिए कई-कई मील पर कोई न कोई मीटर वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि अगर कहीं पर तेल का लीकेज हो, डिफेक्ट हो तो उसका पता वहाँ पर लग सकता है। पता लगने के बाद उसको दुरुस्त किया जाता है। इस तरह से वहाँ की कम्पनी में इस तरह का कोई इंतजाम था या नहीं?

अब सबसे अन्तिम सवाल मेरा यह होगा कि केवल एम०आर०एल० कम्पनी में ही यह बात नहीं है, मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में बरौनी आयल रिफाइनरी तथा भारतीय तेल निगम के कारोबार में लाखों रुपये के तेल चोरी होने के मामले उठते रहते हैं। कई स्रोतों से चोरी होती है लेकिन सरकार ने जाँच नहीं की। फिर चोरी के मामले में जब तक पोलिटीकल संरक्षण नहीं होगा, उन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण जब तक नहीं होगा तब तक यह चोरी हुई नहीं होगी। छोटे लोग तो पकड़े जाएंगे लेकिन जो चोरी करवाने वाले बड़े लोग होंगे इसमें से जो विदेशी कम्पनियों के लोग हैं, उनके मुनाफे जो दूसरे पर चले जाते हैं, यह सारे बड़े बड़े घोटाले जिसके जरिये होते रहे है सरकार को इस पर मजबूती से जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं उस कम्पनी या उन लोगों का एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह तो नहीं है जो ऐसा है जो इस काम में संलग्न हो और भारत को इस तरह से तेल के मामले में क्षति पहुंचाने का काम करता हो और भारत सरकार के तेल निगम आई० ओ० सी० के बड़े अधिकारियों की साठ गाँठ उन लोगों के साथ हो, जो देश के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी करने की नीयत रखते हों।

श्री बलबीर सिंह: डिप्टी चैयरमैन साहब, मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं, उनका जवाब ही गा। जहां तक बड़े अफसरों का सवाल है कि बड़े अफसर इसमें होंगे, उनका हाथ होगा, ऐसी बात नहीं है, न कोई नोटिस में है और न बड़े अफसरों के पास ऐसी बातें हैं किसी किस्म की। बल्कि जितनी भी उन्होंने कार्यवाही की है, उनके अन्दर अगर देखा जाय तो जितने रिमाईंडर्स दिये हैं, जितनी दफा पुलिस कमिशनर को कहा गया है, वे सारे लेटर्स पुलिस कमिशनर को लिखे हैं, ये एक जनवरी, 76, मार्च 78, अप्रेल 78 को लिखे, इनसे मिले हैं, फिर जून 78, जुलाई 78, दिसम्बर 78 में और यह अगस्त 79, नवम्बर 79 तथा दिसम्बर 79, ये सारे पुलिस कमिशनर को और आई जी पुलिस को इन्होंने लिखे हैं। ये सब ऊपर के लेविल पर होता रहा है। सारे बड़े अफसर पूरी तरह से काम करते रहे हैं। आई जी पुलिस को लिखा है और बाकी इस तरह से लिखे हैं। यहां पर के हमारे जो उच्च अधि-

[श्री दलबीर सिंह]

कारी हैं उन्होंने भी लिखा है। अतः किसी बड़े अफसर की कोई इस किस्म की बात कतई तौर पर नहीं है, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बाकी और जो बातें हैं, मैं समझता हूं कि इससे संबंधित नहीं हैं

श्री कल्पनाथ राय : सी बी आई से जांच कराईये।

श्री दलबीर सिंह : इसकी जांच का जहां तक सवाल है, यह सुझाव है अगर जरूरत हुई तो सी बी आई से जांच करा लेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय का जो जवाब स्टेटमेंट में है उससे बिल्कुल साफ होता है कि यह सरकार का दिवालियापन है या इनइफीशियेंसी इतनी हद तक जा सकती है। इसमें यह बात नहीं कि सच सच कबूल कर लें, सच सच कबूल कर लेते कि इतना लास है। हमने फोर्स भी बनायी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन स्पष्ट है कि सरकारी मशीनरी बिल्कुल निकम्मी है और सरकार अपने निकम्मेपन को कबूल कर रही है। उपसभापति महोदय, जब तेल की चोरी होती थी तमिलनाडु सरकार से खतों किताबी बात का सम्बन्ध जोड़ा गया है उसने जवाब में कहा कि एक पैट्रोलियम फोर्स बनायी जाए। सरकार ने पैट्रोलियम फोर्स भी बनायी, 51 आदमी रखे और उसके लिए 2.1 लाख पर एनम देना शुरू किया। परन्तु बावजूद इसके फिर ये कहते हैं कि 16-18 लाख 78-79, 79-80 में घाटा होता रहा है। अब फिर कहते हैं कि चेयरमैन आई ओ सी को भेजते हैं कि यह घाटा हुआ है। यह क्या है?

श्री उपसभापति : प्रश्न पूछिए।

श्री शिव चन्द्र झा : यह स्पष्ट है, उपसभापति महोदय, कि सरकार की मशीनरी बिल्कुल इनएफीशियेंट हैं, चाहे पुलिस फोर्स हो, पैट्रोलियम फोर्स हो या कोई हो। इसमें इन दो की साठ-गांठ है, एक पुलिस की और दूसरी रिफाईनरी वालों की। दोनों की साठगांठ से यह बात चलती है। यदि आपके सामने यह समस्या थी कि चोरी हो रही है घाटा है। तो कोई एक ऐसा भी रास्ता खोजते कि भाई पुलिस वालों से जब नहीं हुआ, अफसर वाले कर रहे हैं तो वे क्या कर रहे है? तो फिर आपने कोई दूसरा रास्ता कहने का मतलब है कि वार फूटिंग पर, मैं साफ कहता हूं मैं उस माने में नहीं कहता हूं लेकिन मिलिटरी के हवाले में, संरक्षण में देने का क्यों नहीं सोचा कि तुम इसका निरीक्षण करो कि चोरी कैसे होती है। मैं इसलिए यह बात उठाता हूं कि मैं बद्रीनाथ की तरफ गया हुआ था। पी डबल्यू डी या इन सबों को सड़क बनाने के लिए दिया गया तो वे लोग इंजीनियर अफसर तक नहीं बना पाते हैं। उन लोगों ने आखिर में कहा कि हम इसको मिलिटरी वालों के हवाले कर देते हैं वे सड़क बनाते हैं, डैम बनाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और मिलिटरी वालों ने कहा कि यह सब काम सिविलियन का है मगर हमको करना पड़ता है क्योंकि वे लोग निकम्मे हैं, करते नहीं हैं। इसलिए मेरा यह एक्सपैरिमैंट के ही रूप में मिलिट्री विंग जो वहां का है, उसमें संरक्षण का, देख-रेख का रास्ता आपने क्यों अख्तियार नहीं किया है?

दूसरा सवाल है कि यहां मद्रास रिफाइनरी में जो अफसर थे, क्या उन लोगों में से किसी को हटाया गया, या उन पर कार्यवाही की गई, या किसी पर आपने एक्शन लिया? और तीसरा

चाहे आपका यह पैट्रोलिंग पुलिस फोर्स हो, या आम पुलिस फोर्स हो, इसके काम करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों में कुछ नया बुनियादी रास्ता चलाया कि यह ठीक से हो . . . (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : पुलिस इन का काम नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : ठीक है। यह मेरे तीन सवाल हैं। मंत्री महोदय एक-एक करके जवाब दे दें।

श्री दलबीर सिंह : श्रीमन्, मैंने बतलाया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह सिक्यूरिटी वहां के इंतजाम के लिए, पकड़ने के लिए, चोरी रोकने के लिए जो भी है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट वहां पर आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो भी हमारे अफसर नीचे से ऊपर तक जो कर सकते थे, वे करते रहे है। उसके बावजूद यह चीजें हुई है। इसलिए यह कहना बड़े अफसरों को हटाने की बात किसी को दोषी पायें तो हटाएं, दोष उनके अन्दर नहीं है तो कैसे हटाएं, कैसे सजा दें उनको। वे सारे लोग लगे हुए हैं, सारे काम को सीरियसली देख रहे हैं और पूरी तरह से इसके ऊपर निगरानी है। लेकिन वह इलाका ऐसा है जो कि . . . (*Interruptions*)

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभापति जी, जो मैंने (*Interruptions*)

. . . . . .

श्री उपसभापति : कृपा करके बैठिये। उनकी बात तो सुनिये।

श्री दलबीर सिंह : तो वह इलाका ऐसा है कि जिसके अन्दर चारों तरफ झुग्गी-झोंपड़ी और मकान बने हुए हैं और किसी वक्त भी आकर वे दांव लगा जाते हैं और यदि पकड़-धकड़ हुई तो दस-बीस आदमी हुए और दो-तीन सिपाही गये, तो धक्का मार के भाग गये। कई दफा ऐसा भी वाक्या हुआ है और वे छीन कर ले भी गये।

तो इसलिए ऐसे स्पाट के ऊपर यह वाक्या है, कोई सब जगह नहीं है। यह तो एक ऐसा स्पाट है जहां पर कि ऐसी बातें हुई है और इस स्पाट को चैक करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी यह होता रहा है और अब इसके ऊपर और भी सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। यह आश्वासन मैं आपको देता हूं।

श्री उपसभापति : यह पूछते हैं कि क्या आप मिलिट्री इसमें लगाएंगे, संरक्षण के लिए, पता लगाने के लिए।

श्री शिव चन्द्र झा : जैसे कि आप फ्लड को रोकने के लिए और दूसरी जगहों के लिए मिलिट्री को डेप्लाए करते हैं।

श्री दलबीर सिंह : हमारा ऐसा विचार नहीं है कि मिलिट्री को डेप्लाए करें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : इस घटना का पूरा उल्लेख इस स्टेटमेंट में नहीं है। घटना ऐसी है कि झोंपड़ी पाईप लाईन के ऊपर थी, बाकायदा नीचे टोंटी लगाई गई जिसको बन्द किया जा सकता था और खोला जा सकता था। नीचे खड्डे जैसा बराबर कमरा बना हुआ था, टैंक। उस टैंक के अन्दर बैठ कर हफ्तों, महीनों से कब तक चुराया गया, पता नहीं। प्रथम तो इसमें जानकारी नहीं

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

दी गई है। शायद मंत्री महोदय ने देखा होगा कि असल में चोरी इस प्रकार की हुई है क्योंकि यह दीखता है कि यह एक छोटी घटना नहीं है, बहुत लम्बे समय से योजनाबद्ध हो रही है और हम लोग पकड़ नहीं पाए ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब रिफाइनरी से तेल पाइपलाइन में चलता है और पोर्ट तक पहुंचता है, तो क्या कम्पैरेटिव कोई चार्ट होता है कि यहां से इतना तेल छोड़ा गया और इतना पोर्ट तक पहुंच गया ? कोई व्यवस्था है कि नहीं ? यदि है, तो नार्मली कितनी परसेन्टेज लीकेज में आप अलाऊ करते हैं, और यह लीकेज जितना आप अलाऊ करते हैं—छीजन—वह बढ़ गया था, इस वास्ते पता लगा कि कहीं न कहीं पर चोरी हो रही है या वैसे ही अकस्मात पता लगा है ।

दूसरे आपने कहा है कि इसकी लैंथ 9.3 किलोमीटर है और 51 आदमी आपने लगाए । बस ठीक है । अगर पैट्रोलिंग वे पैदल ही करते रहते थे, तो मैं यह समझता हूं कि 9.3 किलोमीटर में 51 आदमी यदि पैट्रोल करेंगे चौबीस घंटे तो शायद पैदल नहीं करवाते होंगे । तो उनकी पूरी व्यवस्था है कि नहीं ?

श्री दलबीर सिंह : जहां तक इसकी माप-तौल की बात है श्रीमन्, इसकी पूरी पैमाइश मशीनों से होती है । जहां से तेल जितना निकलता है और आगे जहां तक जाता है पूरी तौर से इसकी पैमाइश होती है और लीकेज वगैरह . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं, जितना पहुंच जाता है . . .

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : पैमाइश का कोई रिकार्ड है ?

श्री दलबीर सिंह : पूरा रिकार्ड है ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : कितना परसेन्टेज है ?

श्री दलबीर सिंह : रिकार्ड है लेकिन उसका पता आखीर में लग सकता है । बीच में नहीं लगता । थोड़ा बहुत में नहीं, जब पूरा चला जाए तब पता लगता है । बीच में पता नहीं लगता है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस बात साफ कर दें . . . (*Interruptions*) आखिर का क्या मतलब है ?

श्री दलबीर सिंह : जब बीच के पाइपलाइन से सारा तेल निकल जाए तब पता लगेगा ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : जब वह तेल खाली होगा । वह कांटिन्युअसली चल रहा है तो पता भी नहीं चलेगा . . (*Interruptions*) .

श्री दलबीर सिंह : श्रीमन्, यह . . . . (*Interruptions*) . . . . . .

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : माथुर साहब, तेल कंटिन्युअसली चल रहा है । खाली कहां से होगा ? माइनस करके बताएं . . . (*Interruptions*) . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रोसेस कांटिन्युअसली है ।

श्री दलबीर सिंह : जितने दिनों से लगातार चल रहा है और जब नोटिस में आया उसके बाद पकड़-धकड़ हुई । उसके ऊपर केस रजिस्टर कराया . . .

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: Is it a continuous process or at times do you measure it?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तेल बराबर पाइपलाइन से बहता रहता है । यह सुबह को छोड़ा रात को बन्द कर दिया ... (*Interruptions*) ... हमारी जानकारी है, प्रोसेस चलता रहता है । आपने कहा, आखिर में पता लगता है । महीने में, छः महीने में, साल भर में कब पता लगा है ?

श्री उपसभापति : ठीक है, वह समझ गए । बता रहे हैं... (*Interruptions*) ... सुन लीजिए पहले ।

श्री दलबीर सिंह : जिस वक्त यह चलता है, जितना हमने यहां रिकार्ड किया और जितना आखीर में रिकार्ड किया . . (*Interruptions*) ...एट द एन्ड ।

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: At the end of the line?

SHRI DALBIR SINGH: At the end of the line. जहां पर टैंकर भरने का इंतजाम है वहां इसका पूरा रिकार्डिंग किया हुआ है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : रोज कितना पाइपलाइन में होकर जाता है उसका रिकार्ड तो होगा ।

श्री दलबीर सिंह : उसका रिकार्ड है, और जो आगे पहुंचता है उसका भी रिकार्ड है। सारा रिकार्ड है... (*Interruptions*) ... इसलिए बीच में जब यह छोटे होल वगैरह कर लेते हैं उसका एक लम्बे प्रोसेस में तो एकदम पता नहीं चलता । इसका सेक्योरिटी वाले या चैकिंग वाले जो हैं उनसे पता लग जाता है । इसलिए सेक्योरिटी और चैकिंग को हमने तेज कर दिया है और श्रीमन्, पुलिस पर इतना खर्च करके, 50 आदमी यहां पर डेप्यूट कराये . . . (*Interruptions*) . . . और बावजूद इसके यह चीज रुकी नहीं है . . . .

श्री सदाशिव बगाईतकर : सभापति जी . . .

श्री उपसभापति : बैठ जाइये, उनको समाप्त करने दीजिए ।

श्री सदाशिव बागाई तकर : . . . कुछ मेकेनिकल इक्वपमेंट आपके पास हैं ?

श्री दलबीर सिंह: मेकेनिकल इक्विपमेंट हैं तभी तो कर रहे हैं, सारा कुछ है । बगैर उसके कैसे होगा ? एक-एक चीज का हिसाब है । मेकेनिकल और टैक्निकल सारी चीजें हैं । इसके बावजूद भी यह जो हम रोक नहीं पाये हैं, मैं सदन को साफ बताना चाहता हूं--हम रोक नहीं पाए--लेकिन हम इसके अन्दर पूरी तरह से कोई न कोई कार्यवाही, हायर लेबल पर जो कुछ मुमकिन हो सकता है, करेंगे, और जो सुझाव मेम्बर साहबान दे रहे हैं उनको ध्यान में रख कर कार्यवाही करेंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : छीजन कितना अलाऊ करते हैं ? लीकेज आप कितना अलाऊ करते हैं ?

श्री उपसभापति : अब नन्दा जी को पूछने दीजिए । जो कुछ बचेगा वह पूछ लेंगे ।

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, this pilferage to which the Government's attention has been called, and on which the hon. Minister has made a statement, makes a fantastic story, and it proves the pathalogical and utter helplessness of a Government that "works". The hon. Minister in the course of his statement, frankly admits:

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

"I am most concerned that all our efforts in this direction have been of little avail."

So, here is a frank admission of total failure to prevent this pilferage. Sir, my question in this context is: Has the percentage of losses sustained as a result of this pilferage been assessed? Does the hon. Minister agree that the loss has been Rs. 1 lakh per day as mentioned in the Calling Attention, or the loss is less or more than the amount mentioned in the Calling Attention? If the loss has been estimated, then what is its money value? The next question is: Has the gang, which has been operating this pilferage throughout the distance of 9.3 kilometres of the pipeline, been identified, prosecuted and punished? If so, how many of them have been so prosecuted and punished? The next question is: What is the real difficulty in preventing this pilferage? We are getting oil from Bombay High right up to the Mathura Refinery, over such a long distance, and we do not hear any story of this kind of pilferage. Here it is only a short distance of 9.3 kilometres from the refinery to the Madras Port. Sir, if you have visited Madras, you must be knowing that it is a most crowded locality. How could this pilferage take place without anybody noticing it, right from the year 1976? Is the IOC thinking of taking effective steps to prevent this? I would also like to know whether it has been found that the IOC officials, the police officers at the lower level and those who were engaged in this pilferage business, had all colluded to do this pilferage. These are the four specific questions which the hon. Minister must answer.

SHRI DALBIR SINGH: Sir, the hon. Member has asked about the losses. I may say that in 1978-79, the losses were Rs. 16.31 lakhs and in 1979-80, Rs. 18.51 lakhs. These are the losses. About security, Sir, as I have already said, the IOC authorities have be[en] very seriously and keenly with t[he] help of the State Government, tryi[ng] to check this, but in spite of this, [as] I have already said it has been hape[ning]. The IOC authorities and the senior officers are always there.

About the steps, I have already ex[-]plained them in the statement.

REFERENCE TO THE REPORTE[D] MISUSE OF OFFICIAL VISIT T[O] CALCUTTA BY A CENTRAL MINISTER

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I wish to make a special mention of a matter which involves not only politics but the Constitution. As you know from the newspapers, the Congress (I) President of West Bengal, Mr. Ajit Panja, gave a call to his followers for a movement against the Left Front Government of West Bengal. They are starting an agitation. It is on, although another section of the Congress (I), led by Mr. Subroto Mukherjee, is not supporting this thing. What brings me to this subject is the behaviour of Central Ministers. A few months ago, the Minister of Irrigation and Power declared publicly that he would not rest until the West Bengal Left Government was thrown into the Bay of Bengal. The Government continues and he also is resting, perhaps doing some other thing. This is going on. A situation is sought to be engineered in the State in order to justify their clamour for the overthrow or dismissal of the West Bengal Left Front Government.

What shocks me is this. On the 1st of this month there was a Calling Attention in this House relating to the Calcutta telephones and telephones in other places. There the Minister for Communications, Mr. C. M. Stephen said: